International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-3 May-June-2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंध 21वीं सदी के विशेष सन्दर्भ में

अभिषेक खोलिया

(शोध छात्र)

रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग

ल. सि. महर रा. स्ना. महाविद्यालय

पिथौरागढ

सारांश "संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के एक अग्रणी वैश्विक शक्ति और शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध भारत–प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरने का समर्थन करता है।" अमेरिकी विदेश और रक्षा सचिवों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच 2़2 मंत्रिस्तरीय वार्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख आवर्ती वार्ता तंत्र है। 2़2 तंत्र के माध्यम से, अमेरिकी और भारतीय अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका–भारत साझेदारी के दायरे में व्यापक पहलों को आगे बढ़ाते हैं। रक्षा और सुरक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने एक मजबूत रक्षा औद्योगिक सहयोग स्थापित किया है जो हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं के सह–विकास और सह–उत्पादन के अवसरों को देखता है। इस वर्ष 2024 की शुरुआत में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में GE F414 इंजन के सह–उत्पादन के लिए एक अग्रणी विनिर्माण लाइसेंस को मंजूरी दी थी। भविष्य को देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने एक शैक्षिक श्रृंखला शुरू की है जो दोनों देशों में रक्षा उद्योगों में योगदान करने के लिए स्टार्टअप और युवा नवप्रवर्तकों को तैयार करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्विपक्षीय अमेरिकी–भारत आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह और रक्षा नीति समूह के माध्यम से भी सहयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा को तैनात करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं, जैसा कि जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा के लिए दोनों देशों के महत्वाकांक्षी 2030 लक्ष्यों में परिलक्षित होता है। हम अपने खनिज सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के रास्ते तलाश रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकें, जिसमें खनिज सुरक्षा साझेदारी भी शामिल है। अगस्त 2023 में, भारत–संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू एंड इमेजिग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म (RE&TAP) ने अपनी उद्घाटन बैठक आयोजित की। इस मंच के तहत, हमारे दोनों देश प्रयोगशाला–से–प्रयोगशाला सहयोग, पायलटिंग और परीक्षण, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के लिए नीति और योजना समन्वय में संलग्न होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और जलवायु कार्रवाई और वित्त जुटाव संवाद के माध्यम से भी सहयोग करते हैं। जून में भारत द्वारा आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, हमने सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण स्थापित किया है।

मुख्य शब्द रक्षा,सुरक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म आदि

प्रस्तावना अब हमारी प्राथमिकताओं में मानव अंतरिक्ष उड़ान, वाणिज्यिक सहयोग और अंतरिक्ष अन्वेषण पर सहयोग को आगे बढ़ाना शामिल है। हम 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास बढ़ाने के लक्ष्य के साथ,

ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण के नासा के प्रावधान की आशा करते हैं। जून में, भारत ने भारत में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल–वेव ऑब्जर्वेटरी के निर्माण के लिए 318 मिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी दी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में समान सुविधाओं के साथ मिलकर अंतरिक्ष–समय में तरंगों को देखने के लिए काम करेगा, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के रूप में जाना जाता है। तरंगें, जो ब्रह्मांड की भौतिक उत्पत्ति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत नागरिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर द्विपक्षीय नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह और क्वाड स्पेस कार्य समूह के माध्यम से सहयोग करते हैं, जिसमें जलवायु और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता डेटा पर जानकारी साझा करने में सुधार शामिल है। बहुपक्षीय सहयोग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, जी20, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) से संबंधित मंचों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों और मंचों पर निकटता से सहयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की सफल G20 अध्यक्षता को मान्यता देता है, जिसमें सितंबर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी शामिल है। शिखर सम्मेलन ने प्रमुख परिणाम दिए जिनमें यूरोप से एशिया तक कनेक्टिविटी के एक नए युग की दिशा में प्रयास, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक स्वतंत्र और खुले इंडो–पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए क्वाड, एक राजनयिक नेटवर्क के रूप में एकत्रित होते हैं। भारत हमारी अर्थव्यवस्थाओं को अधिक कनेक्टेड, लचीला, स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए समृद्धि के लिए इंडो–पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने वाले 12 देशों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत 7 सितंबर को आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हैं। आज भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार है, और जिसकी बैठक अक्टूबर 2023 में कोलंबो में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 मिलियन से अधिक का भारतीय प्रवासी समुदाय दोनों देशों में सहयोग, नवाचार और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण चालक है।

भारत–अमेरिका संबंधों का वर्तमान वर्ष 2000 के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में दस गुना वृद्धि हुई है जो वर्ष 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच गया और वर्ष 2021 में भारत अमेरिका का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि वर्ष 2021 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे महत्त्वपूर्ण निर्यात बाजार है। यह उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष (जतंकम`नतचसने) की स्थिति रखता है। वर्ष 2021–22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में निरंतर विकास, शांति और समृद्धि के लिये IPEF की दक्षता के बारे में दोनों देश समान विचार रखते हैं। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले 'समृद्धि के लिये हिंद–प्रशांत आर्थिक ढाँचा' (Indo&Pacific Economic Framework for Prosperity& IPEF) में भी शामिल हुआ है। हालाँकि रूस–यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान के मुद्दे और ईरान को लेकर दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं में व्यापक विरोधाभास भी रहा है। भारत शीत युद्ध (Cold War) की अवधि में अमेरिकी हथियारों तक पहुँच नहीं बना सका भारत ने पिछले दो दशकों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी हथियार खरीदे हैं। हालाँकि, यहाँ अमेरिका के लिये प्रेरणा यह

रही है कि वह भारत को अपनी सैन्य आपूर्ति के लिये रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता में कमी लाने में मदद दे, जो स्वयं उसके हित में भी है। भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएँ व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों ('युद्ध अभ्यास', 'वज्र प्रहार') में और 'क्वाड' समूह में चार भागीदारों के साथ लघुपक्षीय अभ्यास ('मालाबार') में संलग्न होती हैं। अमेरिका और भारत मध्य–पूर्व एशिया में गठित एक अन्य समूह में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ शामिल हुए हैं जिसे I2U2 (India] Israel] UAE and the US) के रूप में जाना जाता है। इस समूह जो नया क्वाड (new Quad) भी कहा जा रहा है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिये अगले पाँच वर्षों में लगभग 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। इसमें आगे 60,000 भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के साथ–साथ एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिये 4 वर्षों में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना भी शामिल है। भारत के हलके लड़ाकू विमानों के लिये भारत में GE के F414 इंजनों के लाइसेंस अंतर्गत निर्माण के लिये अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत के बीच संपन्न समझौता हाल की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रगति है। यह समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अस्वीकरण (Technology denial regime) के अंत का प्रतीक है। भारत, एक अमेरिकी सहयोगी के रूप में:

दोनों देशों के व्यापक पारस्परिक एवं रणनीतिक हितों के बावजूद चूँकि भारत अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता (non&alignment) का दृष्टिकोण रखता है, इसलिये उसे 'अमेरिकी सहयोगी' (US Ally) नहीं कहा जा सकता। भारतीय नेताओं ने, वे किसी भी राजनीतिक दल के रहे हों, लंबे समय से विश्व के प्रति भारत के दृष्टिकोण की एक केंद्रीय विशेषता के रूप में विदेश नीति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। विशेष रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, भारतीय नेताओं ने अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार का प्रयास किया है, लेकिन इसके लिये विदेश नीति के प्रति भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण से कोई समझौता नहीं किया है। भारत की 'बहुपक्षीय' विदेश नीतिः भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारतीय कूटनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिये 'वसुधैव कुटुम्बकम (world as one family) के दर्शन पर बल दिया है। इस दृष्टिकोण को बहुपक्षीयता या 'बहुसंरेखण' (multialignment) कहा गया है जो जहाँ तक संभव हो सकारात्मक संबंधों की तलाश पर लक्षित है। इस सिद्धांत के अनुरूप ही भारत ने सऊदी अरब के साथ ही ईरान के साथ इजराइल के साथ ही फिलिस्तीन के साथ और अमेरिका के साथ ही रूस के साथ भी अपने संबंधों को सजगता से प्रबंधित किया है। भारत ने उन देशों के साथ भी संलग्नता रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है जो अमेरिका के सहयोगी नहीं हैं (जैसे रूस, ईरान और यहाँ तक कि चीन), यदि उसके राष्ट्रीय हित ऐसी आवश्यकता निर्धारित करते हैं।

भारत–अमेरिका संबंध की आज के समकालीन समय की प्रमुख चुनौतियाँ अमेरिका द्वारा भारतीय विदेश नीति की आलोचना भारतीय अभिजात वर्ग ने लंबे समय से विश्व को गुटनिरपेक्षता के चश्मे से देखा है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही गठबंधन संबंध (alliance relationships) अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रहा है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, विशेषकर शीत युद्ध के दौरान, हमेशा पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका के लिये चिंता का विषय रही है। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने भारत से अफगानिस्तान में सेना भेजने की मांग की थी लेकिन भारतीय सेना ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। वर्ष 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सैन्य समर्थन से इनकार कर दिया था। अभी हाल में भी, रूसी–यूक्रेन युद्ध पर भारत ने अमेरिका के दृष्टिकोण का पालन

करने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप सस्ते रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर जारी रखा है। भारत को 'इतिहास के सही पक्ष' में लाने की मांग को लेकर प्रायः अमेरिका समर्थक आवाजें उठती रही हैं। अमेरिका के विरोधियों के साथ भारत की संलग्नता, भारत ने ईरान और वेनेजुएला के तेल के खुले बाजार पहुँच पर अमेरिकी प्रतिबंध की आलोचना की है। ईरान को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में लाने के लिये भारत ने भी सक्रिय रूप से कार्य किया है। चीन समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB) में प्रमुख भागीदार बने रहने के अलावा भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिये चीन के साथ 18 दौर की वार्ता भी संपन्न की है। अमेरिका द्वारा भारतीय लोकतंत्र की आलोचना विभिन्न अमेरिकी संगठन और फाउंडेशन, कुछ अमेरिकी कांग्रेस एवं सीनेट सदस्यों के मौन समर्थन के साथ, भारत में लोकतांत्रिक विमर्श, प्रेस और धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति को प्रश्नगत करने वाली रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 और भारत पर मानवाधिकार रिपोर्ट 2021 ऐसी कुछ चर्चित रिपोर्ट्स रही हैं। आर्थिक तनाव 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' ने अमेरिका में इस आशंका का प्रसार किया है कि भारत तेजी से एक संरक्षणवादी बंद बाजार अर्थव्यवस्था में परिणत होता जा रहा है। अमेरिका ने जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को प्राप्त शुल्क–मुक्त लाभों की समाप्ति का निर्णय लिया (जून 2019 से प्रभावी), जिससे भारत के दवा, कपड़ा, कृषि उत्पाद और ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे निर्यात–उन्मुख क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।

आज भारत–अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिये क्या किया जा सकता है, बहु–संरेखण के साथ आगे बढ़नाः यूक्रेन–रूस संघर्ष के साथ वैश्विक शक्तियाँ नए समूहों में संगठित हो रही हैं। भारत के लिये रूस और अमेरिका के बीच एक कठिन राह पर चलने की चुनौती है। भारत का दृष्टिकोण अब तक यह रहा है कि अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित में कार्य करे और इसे आगे भी जारी रहना चाहिये। भारत को इस संतुलनकारी कार्य का सामंजस्य करना होगा और प्रबल मतभेदों को दूर करने के लिये संवाद एवं कूटनीति पर बल देना होगा। भारत को उस लगातार बढ़ती खाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिये जिससे विश्व शांति के लिये खतरा ही उत्पन्न हो सकता है। सर्वोत्तम साझा हित का लाभ उठानाः नई भारत–अमेरिका रक्षा साझेदारी एक ऐसे एशिया की कल्पना करना संभव बनाती है जो किसी एक शक्ति के प्रभुत्व के समक्ष असुरक्षित नहीं होगी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की वृद्धि से भारत को अमेरिका के मजबूत समर्थन के साथ चीन के साथ अपनी सैन्य क्षमताओं में भारी अंतर को दूर करने में भी मदद मिलेगी। एशियाई शक्ति संतुलन को स्थिर करने और चीन के उदय एवं एशिया में उसकी आक्रामकता से उत्पन्न भूराजनीतिक मंथन से निपटने में भारत और अमेरिका दोनों ही गहन हित रखते हैं। आर्थिक अंतर्संबंधः भारत–अमेरिका आर्थिक संलग्नता को निवेश एवं व्यापार के वृहत प्रवाह के साथ और अधिक स्थिरता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। भारत में अमेरिकी निवेश 54 बिलियन डॉलर आँका गया है जो इसके वैश्विक निवेश के 1% से भी कम है। इसके साथ ही, भारत को भी अमेरिका में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच परस्पर निर्भरता का सृजन करना महत्त्वपूर्ण है। भारत के लिये विनिर्माण–आधारित निर्यात वृद्धि और अवसंरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करके एक विकसित राष्ट्र बनने के लिये अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अमेरिकी बाजार तक अधिक पहुँच और प्रौद्योगिकीय सहयोग के बिना यह सफल नहीं हो सकता। भारत–अमेरिका CET सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है। भारत का आर्थिक उत्थान अमेरिका के उतने ही हित में होगा

जितना कि प्रौद्योगिकी सक्षमकारिता एवं वैश्विक मामलों में अमेरिका का नेतृत्व भारत के हित में। इस वास्तविकता को विश्व मंच पर भारत की तटस्थता और नाटो जैसे गुट से संबद्ध होने से इसके इनकार के शोर में नहीं खो नहीं जाना चाहिये।

निष्कर्ष भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन के दौरान कहा कि "पिछले कुछ वर्षों में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई प्रगतियाँ हुई हैं। इसके साथ ही, एक अन्य यानी अमेरिका एंड इंडिया में और भी महत्त्वपूर्ण विकास हुए हैं।'' उनका यह वक्तव्य हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों को भलीभांति प्रकट करता है। ''हालाँकि रूस, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के मामले में भारत और अमेरिका की नीतियाँ अलग–अलग हैं, चीन एक ऐसा हित है जो दोनों देशों को एक साथ संरेखित करता है और इसलिये सहयोग की एक अच्छी संभावना प्रदान करता है।''वर्तमान में भारत–अमेरिका संबंधों में सुधार हो रहा है जिससे कई आधिकारिक दौरे हो रहे हैं। यद्यपि इतिहास का बोझ है, फिर भी भारत अब अमेरिका को ''हस्तक्षेपवादी'' के रूप में नहीं देखता है। इसका एक कारण नई दिल्ली में गैर–कांग्रेसी सरकारों की मौजूदगी भी हो सकती है। अपनी अनेक घरेलू समस्याओं के बावजूद भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। चीन के साथ अमेरिकी संबंधों में खटास आने पर इसे एशिया में एक विश्वसनीय और संभावित साझेदार के रूप में भी देखा जाता है। बुश शासन ने भारत को ''फिर से खोजा'' है। अमेरिका में भारत की छवि को 'गरीबों की भूमि' से 'दिमागों के देश' तक बढ़ाने में भारतीय अमेरिकियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए एनआरआई की विशेष रूप से प्रशंसा की जाती है। वे इंडिया कॉकस के माध्यम से पहले की तुलना में बेहतर संगठित हैं, जिसमें अब प्रतिनिधि सभा के 130 सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार भविष्य आशावाद से भरा है। आतंकवाद, विशेषकर साइबर आतंकवाद से निपटने पर एक समान ध्यान केंद्रित है। दोनों देशों को विभाजित करने वाले कोई प्रमुख रणनीतिक मुद्दे नहीं हैंय सबसे बढ़कर, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है। आर्थिक स्तर पर व्यापार और निवेश प्रवाह अधिक होने की संभावना है। लेकिन, क्षमता का दोहन करना भारत का काम है। गैर–सैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग एक अन्य ग्रीनफील्ड क्षेत्र है। साथ ही, अमेरिका को अपनी ओर से दो मोर्चों पर सतर्क रहना चाहिए, लोकतंत्र निश्चित रूप से सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण सामान्य संरचनात्मक कारक है। सामान्य राजनीतिक प्रणालियाँ संबंधों को आसान बनाती हैंय उनके यात्रा करने की संभावना कम है। यह ठीक इसी कारक के कारण है कि भारतीय अमेरिकी आसानी से अमेरिका में रहने के लिए अनुकूल हो सके। रक्षा खरीद के संबंध में भारत अमेरिका के साथ सहज नहीं हैय कई शर्तों के साथ उन्हें वितरित करने में काफी समय लगता है। वहीं, रूस के साथ काम करने का अनुभव आरामदायक रहा है.

जहां तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन का सवाल है, इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। समाधान वैश्विक होना चाहिए लेकिन वाशिंगटन को नई दिल्ली के मामले का समर्थन करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 कोहेन, स्टीफन पी. (जनवरी 2010) महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष पाकिस्तान और शीत युद्ध (पीडीएफ) ब्रूकिंग्स. पीपी. 76, 77, 78. आईएसबीएन 978–0–415–55025–3.

2 गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम), मिशन, और तथ्य ब्रिटानिका'' britannica-com 12 मई 2023 । 21 मई 2023

3 ग्रेरे, फ्रेडरिक (27 जुलाई, 2019) ''भारत–अमेरिका संबंधों के तीन दशकों को देखते हुए''

4 भारत के दूतावास, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में आपका स्वागत है'' 26 मार्च 2016 को मूल से संग्रहीत 2 अप्रैल 2016,

5 भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत'' (पीडीएफ) dpcc-co-in . 4 मई 2012 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत 25 मार्च, 2018 को लिया गया।

6 मोदी सरकार का एक सालः हम बनाम वो'' इंडियन एक्सप्रेस . 25 मई 2015.

7 ओबामा–मोदी वार्ता के बाद भारत–अमेरिका संयुक्त बयान'' हिन्दू 25 जनवरी 2015.

8 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर भारत–अमेरिका में खींचतान राजनयिक 11 जून 2015.

9 सुमित, गांगुली (2022) ''ओबामा, ट्रम्प और मोदी के अधीन भारतीय विदेश नीति'' प्रकृति सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संग्रह 59 (1) 9–23. डीओआई 10.1057एस 41311–021–00294–4,

10 भारत, अमेरिका ने प्रमुख रक्षा साझेदार समझौते को अंतिम रूप दिया'' इंडियन एक्सप्रेस 9 दिसंबर 2016.